STATEMENT BY PRIME MINISTER

Re. His recent visit to Russia, USA, UN and UK

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सभापति महोदय, मैंने 4 नवम्बर से 13 नवम्बर 2001 तक रुस, अमेरिका और ब्रिटेन का द्विपक्षीय दौरा किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 56वें सत्र को संबोधित किया । मैं महासभा से कुछ समय निकाल कर अर्जेन्टिना, साइप्रस और ईरान के राष्ट्रपतियों तथा मारिशस के प्रधान मंत्री से भी मिला ।

इन दौरों और बैठकों में इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक और दीर्घकालीन एजेंड़ा पर ध्यान केन्द्रित किया गया । इनसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाने और अफगानिस्तान में युद्ध के बाद की चुनौतियों से निपटने पर विचार-विमर्श करने का भी मौका मिला ।

रुस के मेरे शासकीय दौरे का उद्देश्य अक्तूबर,2000 में राष्ट्रपति पूतिन की भारत यात्रा के दौरान वार्षिक शिखर बैठकों के बारे में लिए गए द्विपक्षीय निर्णयों को पूरा करना था ।

रुसी नेताओं के साथ हुई मेरी बातचीत से हमारे भौगोलिक-स्ट्रॅटेजिक दृष्टिकोण के औचित्य की पुष्टि हुई है और हमारी द्विपक्षीय स्ट्रॅटेजिक भागीदारी सुदृढ़ हुई है । इनमें आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौघोगिकी, रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने की व्यापक गुंजाइश पर भी प्रकाश ड़ाला गया ।

इस दौरे के दौरान आतंकवादियों पर मास्को घोषणा और हमारे द्विपक्षीय संयुक्त बयान जारी किए गए तथा कई समझौते हुए जिनसे हमारे भावी सहयोग की रुपयरेखा तैयार हुई । हमने घनिष्ठ रक्षा सहयोग तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की ।

हमने अपने व्यापार में विविधता लाने के साथ-साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी चर्चा की । हमें ऋण की रुपए में वापिस-अदायगी पर आधारित भारतीय निर्यात में प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिए सूचना प्रौघोगिकी, आधारमूत ढ़ांचे, औषधि और हीरे जैसे व्यापार के उभरते नए क्षेत्रों को सक्रिय रुप से विकसित करने की जरुरत है । इसके साथ-साथ चाय और तंबाकू जैसी परम्परागत वस्तुओं के रुसी आयातय को जारी रखा जाना चाहिए । हमने भारतीय उघमों में किए गए रुसी निवेश के लिए रुपए में आदायगी हेतु धनाराशि रिलीज़ करने पर भी चर्चा की ।

हमने ऊर्जा सुरक्षा पर ठोस द्विपक्षीय बातचीत करने पर भी चर्चा की जिसकी हमें शीघ्र ही शुरु होने की आशा है । सखलिन परियोजना में भारत द्वारा किया गया निवेश इस क्षेत्र में हमारे सहयोग की शुरुआत का परिचायक है ।

रुस के विभिन्न शहरों की शैक्षिक संस्थाओं में भारतीय अध्ययन की चार पीठों की स्थापना की गई है । गुजरात और अस्त्रखान क्षेत्र के बीच तथा हैदराबाद और कज़ान शहर के बीच भागीदारी के समझौते किए गए हैं । इन समझौतों से दोनों देशों के लोगों के मध्य आपसी संबंध, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सहयोग और मज़बूत होंगे । मार्च 2000 के बाद भारत और अमेरिका ने अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिए व्यापक बातचीत की है । राष्ट्रपति जार्ज

ङब्ल्यू. बुश के निमन्त्रत्र पर मेरी वाशिंगटन यात्रा के दौरान दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में इस बातचीत की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया। राष्ट्रपति बुश ने जोर देकर यह बात कही कि उनका प्रशासन हमारे द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक आधार पर सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबंद्ध है।

हमने द्विपक्षीय आर्थिक बातचीत को जारी रखने और उसे व्यापक बनाने तथा ऊर्जा, पर्यावरण स्वाथ्य जैव-प्रौघोगिकी और सूचना प्रौघोगिकी क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की । हम अंतरिक्ष कार्यक्रमों तथा नागरिक नाभिकीय सुरक्षा परियोजनाओं में सहयोग करने पर भी शीघ्र ही चर्चाएं शुरु करेंगे।

भारत-अमेरिकी रक्षा नीति दल को फिर से सक्रिय बनाया गया है और इस दल की दिसम्बर में बैठक होगी। हमने द्विपक्षीय उच्च प्रौघोगिकीय व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा दोहरे उपयोग वाले और सैन्य उपकरणों के हस्तांतरण की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के तरीकों पर बातचीत करने पर सहमति व्यक्त की। आर्थिक और प्रौघोगिकी प्रतिबंध हटने से इस प्रक्रिया में मदद मिलेगी।

मैंने अमेरीकी कांग्रेस के अनेक सदस्यों से व्यापक बातचीत की । मैं हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्ज और सीनेट के दोनों दलों के नेताओं, हाउस इंटरनेशनल रिलेशन्स कमेटी तथा सीनेट फोरेन रिलेशन्स कमेटी के सदस्यों से भी मिला। भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय स्वरुप के समर्थन पर पुनः बल दिया गया।

इस यात्रा से भारत-अमेरिकी संबंधों में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। द्विपक्षीय तथा व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इनका विस्तार होने और विविधता लाने की बेहतर दीर्घकालीन संभावनाएं हैं।

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर ने मेरे न्यूयॉर्क से दिल्ली लौटते समय मुझे एक दिन के शासकीय दौरे पर लंदन में रुकने के लिए आमंत्रित किया था।

प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर और मैंने नई दिल्ली में अक्तुबर में उनके संक्षिप्त प्रवास के दौरान हुई अपनी बातचीत को जारी रखा। हमने द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं की समीक्षा की जिनमें हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इन चर्चाओं को जारी रखते हुए निकट भविष्य में उस समय विस्तारपूर्वक बातचीत होगी जब प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर भारत के शासकीय दौरे पर आएंगे। हमें उम्मीद है कि उनका यह दौरा अगले साल जल्दी ही होगा।

मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए अपने भाषण में हम सभी के लिए चिंता के दो प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला था - अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सभ्य समाज के लिए खतरा तथा समान विकास की चुनौती। लोकतांत्रिक और बहु-सांस्कृतिक विकासशील देशों में आतंकवाद तथा विकास एक दूसरे के बिलकुल विपरीत हैं।

हमें अंतराष्ट्रीय और राष्ट्र द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की परिभाषा अथवा उसके मूल कारणों पर अस्पष्ट और निरर्थक तर्कों को नकारना होगा। 11 सितम्बर की घटना के बाद आतंकवाद के विरुद्ध बनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का सभी प्रकार के आतंकवाद को एकनिष्ठ होकर समाप्त करने के लिए लाभ उठाया जाना चाहिए।

विकासशील देशों को हाल में भूमण्डलीकरण का उनके देश की गरीबी के स्तर और आय के अन्तर पर पड़ने वाले प्रभाव की कुछ कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा है । दोहा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के सम्मेलन में जो परिणाम सामने आए हैं, उनमें भी विकास पर विश्व वार्ता शुरु करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है । गरीबी उन्मूलन के लिए संसाधन जुटाने को इस वार्ता में उचित स्थान दिया जाना चाहिए । इसमें न केवल गुट निरपेक्ष आंदोलन तथा समूह-77 के देशों के आर्थिक एजेंडा को ही नहीं बल्कि उत्तर-दक्षिणी देशों के संबंधों को भी प्रमुखता दी जानी चाहिए ।

मैंने अपनी समस्त द्विपक्षीय चर्चाओं में यह महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अफगानिस्तान की स्थिति तथा उसके भविष्य के बारे में व्यापक दृष्टिकोण पर समान विचार थे । आतंकवाद को किसी भी राजनैतिक, आर्थिक या वैचारिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता । वस्तुतः आतंकवाद के खिलाफ अभियान में किसी मज़हब को लक्ष्य नहीं बनाया गया है ।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी कि आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने वाले सभी स्त्रोतों तथा उन्हें पनाह देने वाले सभी स्थानों को सभी जगह पूरी तरह से बंद कर दिया जाए ।

इसी प्रकार अफगानिस्तान में एक व्यापक जनाधार वाली प्रतिनिधिक, स्वतंत्र तथा तटस्थ सरकार के गठन की आवश्यकता पर समान विचार उभर कर सामने आए । वहां पर पुनर्निर्माण कार्यों के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरुरत पर भी बल दिया गया । अफगानिस्तान के राजनीतिक तथा आर्थिक भविष्य के बारे में भारत के न्यायोचित हित को व्यापक समर्थन मिला ।

इस बात को आम तौर पर स्वीकार किया गया कि अफगानिस्तान में भावी राजनीतिक ढ़ांचे और आर्थिक एजेंडा पर परामर्श करने के लिए 6+2 समूह की अपेक्षा एक व्यापक प्रतिनिधित्व वाल ढ़ांचे की जरुरत है । इसके बाद, 16 नवम्बर को भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुई 21 देशों की बैठक में भाग लिया जो अफगानिस्तान की स्थिति पर विशेष रुप से चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी ।

हम अफगानिस्तान में भावी राजनीतिक तथा मानवीय व्यवस्थाओं के बारे में अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे । हम अफगानिस्तान की सरकार तथा वहां के सभी लोगों के साथ एकता के पारम्परिक संबंधों को कायम रखते हुए उन्हें सुदृढ़ भी बनाते रहेंगे । धन्यवाद ।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) **:** सभापति जी, जो वक्तव्य प्रस्तुत हुआ उसके कुछ अंश प्रधानमंत्री महोदय ने पढ़े नहीं हैं । क्या वे इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं?

एक माननीय सदस्य : पढ़ नहीं सकते, यह मान लीजिए ।

श्री बालकवि बैरागी : अंतिम प्रश्न ।

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल) **:** ताली बजाने वालों की तरफ देखा था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान आकृष्ट किया ।

श्री दीपांकर मुखर्जी : आप तालियों से भ्रमित हो गए थे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: माननीय सदस्यगण, आप इस बात से सहमत होंगे कि यघपि पिछले लगभग 15 दिनों में अफगानिस्तान की स्थिति में जबरदस्त बदलाव आया है और संयुक्त मोर्चा/नार्दन एलाइंस राजधानी - काबुल सहित अफगानिस्तान के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में घुस गए हैं, फिर भी स्थिति अस्थिर है और तेजी से बदल रही है ।

सरकार इस स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है और सभी संबंधित पक्षों और समूहों से लगातार संपर्क बनाए हुए है । धन्यवाद ।

श्री बालकवि बैरागी : फिर भी एक पैराग्राफ नहीं पढ़ा है ।

एक माननीय सदस्य : उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

श्री बालकवि बैरागी : एक पैराग्राफ फिर भी रह गया है । माननीय प्रधानमंत्री महोदय इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं या इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए क्या परिस्थिति है माननीय सभापति महोदय?

एक माननीय सदस्य : सभापति जी, पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

MR. CHAIRMAN; In the Business Advisory Committee, we will decide about the form of debate, whether it should be a Short Duration Discussion or a Discussion on the Statement. It was decided yesterday in the meeting. Now, we will continue with the Explosive Substances (Amendment) Bill, 1999.

The Explosive Substances (Amendment) Bill, 1999 -*Contd.*

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT (Gujarat): Sir. in this Bill, provisions have been made to make it deterrent and to enhance the punishments for various offences, under different clauses. An effort has been made to make deterrent provisions in the Bill in order to deal with those persons who are in possession of explosives or those who are importing RDX and things like that. There is no opposition to that. When provisions are made deterrent to contain such activities, everybody would agree to it. But, Sir, I would bring to the hon. Minister's notice some glaring examples of what happened in Gujarat. Gujarat is a border State. Some time before, information was given to the police in Kutch that a huge quantity of RDX and other things had been brought to the Kutch. Sir, the BSF and other forces, numbering 1,200, tried to find out the material and the persons who had brought it. They were in_ search of the material. Sir, 1,200 police personnel surrounded the area. They said that the people who had brought these would be booked. They traced the footprints of camels. The material was brought on camels.